Scientific Organisations and other connected organisations, to review the progress made thereunder and to consider proposals fort the sanction of grant-in-aid for conducting research connected with the sugar industry and other related matters.

भारतीय खाद्य निगम को मजदूरों की सप्लाई

1436. **श्रीमती सत्या बहिन :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय भारतीय खाद्य निगम को मजदूरों की सप्लाई करने वाले ठेकेदारों की संख्या कितनी है और इन ठेकेदारों द्वारा अब तक भारतीय खाद्य निगम को अनुमानत: कितने मजदूरों की सप्लाई की गई है ; और

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि ठेके के आधार पर काम करने वाले मजदूरों को न्यूनतम वेतन व श्रम से संबंधित अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने कुल 1500 डिपुओं में से 702 डिपुओं में हैंडलिंग और परिवहन ठेकेदार सीधे ही नियुक्त किए हैं । इसके अतिरिक्त; खाद्यान्नों की खरीफ और रबी वसूली के दौरान मंडियों में ठेकेदारों की मौसमी नियुक्तियां भी की जाती हैं । कार्य के भार पर निर्भर करते हुए, ठेकेदारों द्वारा नियुक्त किए गए श्रमिकों की संख्या सामान्यतया प्रति दिन 50,000 से 1,00,000 व्यक्तियों के बीच भिन्न-भिन्न होती है ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा ठेकेदारों के साथ निष्पादित ठेकों के उपयुक्त प्रावधान सम्मिलित कर न्यूनतम वेतन और अन्य अनुषेय सुविधाएं सुनिश्चित की जाती हैं ।

Production by Sugar Mills in Uttar Pradesh

1437 -SHRI ASHWANI KUMAR : Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether the sugar mills eurrently operating in Uttar Pradesh an only to draw 33 per cent of the total available cane;

(b) whether this drawal percentage is lest than the national average; if not the extent therof; and

(c) what steps Government propose to take to increase the percentage of drawal of Uttar Pradesh to bring it to the national average?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD (SHRI TARUN GOGOD : (a) and (b) As per the figures of 1990-91 season complied on a provisional basis, it is seen that the drawal percentage of sugarcane by the sugar factories in Uttar Pradesh was 31.6% as against the national average of 50.9%.

(c) Government had issued a number of licences for setting up of new sugar factories and expansion in the capacities of existing sugar factories in the State of Uttar Pradesh during the 7th Five Year Plan period. Government had also announced an incentive scheme for early crushing according to which sugar production achieved during the period 01-10-1991 to 15-11-91 would be entitled to freesale at 72%, as against the normal 55%, so as to induce sugar fac-totries to commence early crushing and thereby crush more sugarcane during the season.

विभिन्न क्षेत्रों का निजीकरण

1438. **मौलाना अबेदुल्ला खान आजमी :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में निजीकरण शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?